

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी- श्री इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या- 30/2018

बउनवान

जवाहरी आयु 60 वर्ष पुत्र श्री चतुर्भज जाति-मेघवाल निवासी-लिसाडिया
तहसील-बारां जिला-बारां (अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार, बारां (रेस्पोंडेंट)

अपील धारा-75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :-1. श्री बृजराज सिंह चौहान, अभिभाषक (अपीलांट)
2. परोकार सरकार (रेस्पोंडेंट)

निर्णय दिनांक- 27.01.2020

1- अपीलांट ने जयें अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 08.10.2015 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा-75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम-लिसाडिया तहसील-बारां की आराजी खसरा नम्बर 66 रकबा 0.20 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 100/-रूपये अर्थदण्ड एवं 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों के प्रतिकूल होने से काबिल खारिज योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुनवायी जवाबदेही का अवसर दिये बिना स्वतंत्र साक्ष्य लिये अपीलांट की अनुपस्थिति में एकतरफा निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। अपीलांट का अतिक्रमित आराजी पर कोई कब्जा नहीं है ना ही कोई सरकारी तावान बकाया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरुद्ध विधि विरुद्ध आदेश पारित करने में भारी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 08.10.2015 निरस्त फरमाया जावे।

2- इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जयें सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर अभिभाषक अपीलांट व परोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

3- बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को ना तो विधिवत नोटिस जारी किया है ना ही सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर दिया है, एकपक्षीय निर्णय पारित किया है। अपीलांट का विवादित आराजी पर कोई कब्जा नहीं है, कब्जा काफ़ी

समय से छोड़ रखा है। साथ ही कथन किया कि हल्का पटवारी ने अपीलान्त को विरुद्ध बिना मौके देखे व कब्जे की जाँच किये बिना अधीनस्थ न्यायालय में रिपोर्ट पेश की गयी है, इसी आधार पर अपीलान्त को सजायाब किया गया है, जो विधि विरुद्ध है। वर्तमान में अपीलान्त को कोई कब्जा काश्त नहीं है ना ही उसके विरुद्ध कोई तावान राशि बकाया है। अपीलान्त भविष्य में भी उक्त आराजी पर कभी कब्जा नहीं करने के लिए वचनबद्ध है। अतः अपीलान्त की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 08.10.2015 निरस्त फरमाया जावे।

4- इसके विपरीत परोकार सरकार ने अपीलान्त के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलान्त विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त को उक्त आराजी पर पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 275/14 निर्णय दिनांक 03.03.2014 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

5- हमने विद्वान अभिभाषक अपीलान्त व परोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्त को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। किन्तु बहस के दौरान अभिभाषक अपीलान्त का कथन रहा है कि उसने उक्त आराजी से कब्जा छोड़ दिया है, ऐसी स्थिति में अपीलान्त के प्रति सहानुभूति व नरमी का रूख अपनाते हुये सशर्त सजा माफ किया जाना उचित समझते है।

6- परिणामस्वरूप, अपीलान्त की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा निर्णय दिनांक 08.10.2015 से पारित बेदखली एवं शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 1159/15 में पारित निर्णय दिनांक 08.10.2015 से दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर माफ की जाती है कि अपीलान्त विवादित आराजी से कब्जा छोड़ दें तथा तहसीलदार, बारां के समक्ष दो माह में उपस्थित होकर अण्डरटेंकिंग पेश कर दे कि उक्त आराजी पर भविष्य में अतिचार नहीं करेंगे तथा तहसीलदार, बारां कब्जा छोड़ने से सन्तुष्ट हो जावे तो अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा निर्णय दिनांक 08.10.2015 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है, अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां का उक्त निर्णय यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 27.01.2020 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर, बारां

